उल्लेखनीय है कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियां उन कार्यालयों में गठित की जाती हैं जिनमें (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) 25 से अधिक कर्मचारी हों ।

(ख) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के वास्ते राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए जारी किया गया वार्षिक कार्यक्रम कृषि मंत्रालय द्वारा अपने अधीन कार्य कर रहे सभी कार्यालयों, संस्थानों आदि को भेजा गया था । रोजमर्रा कार्यों में राजभाषा का उपयोग बढ़े यह सुनिश्चित करने के लिये सभी संबंधित कार्यालयों, संस्थानों आदि को उक्त वार्षिक कार्यक्रम लागू करने का निदेश दिया गया था । वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा निरीक्षणों के जरिए नजर रखी जाती है । तिमाही प्रगति रिपोर्टों को समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी सलाहाकार समिति की बैठकों में की जाने वाली समीक्षा भी शामिल है । जहां वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियां पाई जाती हैं । उन कमियों को जहां तक सम्भव हो सके दूर करने के लिये कार्रवाई की जाती है । मंत्रालय इन उपायों के जरिए 1985-86 के लिये वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आशा रखता है ।

(ग) ऐसे कोई कार्यालय या संस्थान नहीं हैं जिनमें सारा काम राजभाषा में किया जा रहा है ।

(घ) कार्यालयों या संस्थानों के काम की किस्म, इस समय वहां के सभी कर्मचारियों को राजभाषा के इस्तेमाल की प्रवीणता प्राप्त न होने और आशुलिपि एवं टाइपिंग आदि की सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण अभी तक किसी भी कार्यालय को राजभाषा में सारा काम करने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है । वैसे, रोजमर्रा कार्यों में राजभाषा का उपयोग बढ़ाने की दृष्टि से कुछेक ऐसे अनुभागों और विषयों का चयन करने के लिये कार्रवाई की जा रही है, जिनमें सारा कार्य राजभाषा में ही किया जा सकता हो ।

Plots for weaker sections of the Society in DDA Schemes

1948. SHRI NAND KISHORE BHATT: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state whether Government are considering any proposal to release smalt plots for weaker and middle sections of the society in DDA residential schemes other than the Rohini Scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): A "Scheme for providing developed plots for self-help housing to lower strata of the society economically weaker sections including squatters linked with affordability", has been included in the Seventh Five Year Pran for the Union Territory of Delhi as a development scheme of DDA.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद

1949. **श्री अच्छेलाल बाल्मीक** : क्या शहरी **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के कई पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके अतिरिक्त काडर पुनरीक्षण के पश्चात् कुछ और रिक्तियां भी भरी जानी हैं; यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 15 से 20 वर्ष की सेवा के पश्चात् भी सहायक अभियन्ता (सिविल) पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं ?

(घ) सरकार नियमित पदोन्नतियां देकर अधिशासी अभियन्ताओं के पद कब तक भरने का विचार रखती है ; और

(ङ) सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति पाने के लिए पात्रता की निर्धारित अवधि क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह): (क) जी हां, 32 पद रिक्त पड़े हुए हैं ।

(ख) जी हां, ऐसे पदों की संख्या 37 हैं ।

(ग) 15/20 वर्षों की सेवा वाले कुछ सहायक इंजीनियर (सिविल) पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं ।

(घ) कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है । तथापि, इस मामले को शीघ्रता से अन्तिम रूप दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ङ) इंजीनियरी में स्नातक सहायक इंजीनियरों के लिए निर्धारित पात्रता अवधि 8 वर्षों की है और डिप्लोमा होल्डर सहायक इंजीनियरों के लिए यह अवधि 10 वर्षों की है ।

Urban Basis Services rrogramme

1950. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have launched an Urban Basic Services Programme to improve the quality of life of the urban poor;

(b) whether the programme has been launched with the help of the State Governments and UNICEF;

(c) if so, what are the main features of the programme; and,

(d> what is the number of areas proposed to be covered dining the period 1986-87?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALB1R SINGH): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The Scheme is intended to improve awareness and to motivate collective community Organisations in improving quality of life in general and the development of children and women of the low-income urban families in particular. The expenditure on the Scheme will be shared among the UNICEF, State Government and the Central *Govt,* in the ratio 40:40: 20.

The UNICEF have pledged an assistance of US $9.2 millions under this Scheme.

(d) It is proposed to cover 36 districts in various States and Union Territories under this Schema.

Concurrent evaluation of IRDP

1951. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state;

(a) whether a concurrent evalua tion of the integrated rural develop ment programme has shown that in 28 per cent of the cases, assets" created with the help of the programme are not intact with the beneficiaries;

(b) if so, what are the other points found by the evaluation;

(e) whether the data of concurrent evaluation of IRDP were being collected by 29 reputed organisations in the country from '36 districts- since 1985; and

(d;> if so, what are the results of the survey for October-November, 1985 and what steps the Central Government propose to take in view of the drain of assets in the seheme of IRDP?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BUTA SINGH): (a) The concurrent evaluation report of 36 selected districts in October-November, 1985 has found that 28 per cent of the sample beneficiaries did not have the assets intact at the time of survey.

(b) to (d) The data is being collected from October-November. 1985.

Some of the major findings in the October-November, 1985 concurrent evaluation report are summarised below ;-

(i) more than 60 per cent of the sample beneficiaries had been identified *in* the Gram Sabhas;